



संक्षिप्त समाचार

सीएम ने प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल की माताजी की कुशलक्षेम पूछी संवाददाता देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सिनर्जी अस्पताल में जाकर भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल की माता जी की कुशलक्षेम पूछी। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे। एम्बुलेंस चालक ने लगाई फांसी, चिकित्सालय पर लगाया उत्पीड़न का आरोप संवाददाता देहरादून। सरकारी चिकित्सालय में एम्बुलेंस चालक के पद पर कार्यरत युवक ने सरकारी आवास में गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने अस्पताल के ही चिकित्सक पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जसवंत सिंह गुसाईं यहां प्रेमनगर स्थित राजकीय चिकित्सालय में एम्बुलेंस चालक के पद पर कार्यरत था तथा वह वहीं पर सरकारी आवास में अपनी पत्नी व दो बच्चों के साथ रहता था। गत दिवस जसवंत की पत्नी व बच्चे शाम को घूमने चले गये तो उसने पीछे से गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर उसकी तलाशी ली तो पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने चिकित्सालय के ही एक डाक्टर पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। दिव्य धाम आश्रम, में 'भारतीय नववर्ष उत्साह से मनाया गया संवाददाता देहरादून। डीजेजेएस द्वारा नई दिल्ली के दिव्य धाम आश्रम में 'मासिक आध्यात्मिक कार्यक्रम' आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम ऊर्जा, दिव्यता व सकारात्मकता से ओतप्रोत था। आध्यात्मिक विकास हेतु लाभाभिवृत्त होने के लिए बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु एकत्रित हुए। कार्यक्रम का आरम्भ वेद-मंत्रोच्चारण द्वारा हुआ, जिसने भारतीय नववर्ष के शुभ आगमन (विक्रम संवत्- 2079) हेतु एक आदर्श, शांतिपूर्ण व अनुकूल वातावरण को निर्मित किया। कू ऐप बना दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संवाददाता देहरादून। देश के पहले बहुभाषी माइक्रो-ब्लॉगिंग मंच कू ऐप ने स्वेच्छिक सेल्फ-वेरिफिकेशन फीचर लॉन्च किया है और इसके साथ ही यह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है। कोई भी यूजर अब अपने सरकार द्वारा स्वीकृत पहचान पत्र का इस्तेमाल करके चूटकियों में प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल को सेल्फ-वेरिफाई कर सकता है। स्वेच्छिक सेल्फ-वेरिफिकेशन असल आवाजों की दृश्यता को बढ़ावा देता है।

उत्तराखंड की सरकार आम आदमी की सरकार बनेगी

स्थापना दिवस

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को चौधरी फार्म हाउस, जी.एम.एस रोड, देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जीएमएस रोड से घंटाघर तक भाजपा की शोभा यात्रा में भी प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा हमारा संगठन राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम के सिद्धांत पर चलता है। डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रवाद की भावना पूरे देश में जगाई। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई के

पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस पर शोभायात्रा भी निकाली



सपनों को आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भाजपा जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा हमारी पार्टी ने हमेशा प्रत्येक कार्य को अनुशासन के साथ पूर्ण करने का सिद्धांत दिया है। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई का स्मरण करते हुए कहा कि अटल जी की वजह से उत्तराखंड अलग राज्य बना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

के मार्गदर्शन में राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है। पूरे मनोयोग से काम करना जनहित की सेवा करना ही हमारी प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही कई संकल्प लिए गए हैं। राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य करेगी। सरलकरण, समाधान एवं निस्तारीकरण पर अधिकारियों को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी प्राथमिकता हमेशा ही अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार एवं प्रशासन की सेवा पहुंचाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता से किए वायदे के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही उत्तराखंड में लागू करेंगे। सरकार ने पर्यावरण मित्रों का एक दिन का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। नए बजट में सरकार ने गरीब परिवारों हेतु एक साल में तीन सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया है, जो पूरा किया जाएगा।



उत्तराखंड देव भूमि, योग भूमि के साथ ही वीर सैनिकों की भूमि भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेशन योजना पर बड़ा फैसला लेते हुए अब पति-पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेशन योजना का लाभ दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, उन्हें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा। अन्वोदय के आदर्श वाक्य पर काम करते हुए हम समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से ऊपर उठाने का काम करेंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, भाजपा महामंत्री संगठन अजय कुमार, विधायक श्रीमती सविता कपूर, खजान दास, विनोद चमोली, मेयर सुनील उनियाल गामा, भाजपा के महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

खतरे में राज्य आंदोलनकारी कोटे की नियुक्तियां!

सुनवाई

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को किया निरस्त

संवाददाता

देहरादून। हाई कोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के मामले पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार के प्रार्थना पत्र को यह कहकर निरस्त कर दिया। कहा कि आदेश को हुए 1403 दिन हो गए। सरकार अब मोडिफिकेशन एप्लिकेशन पेश कर रही है। अब इसका कोई आधार

आरक्षण दिया जाना असंवैधानिक

न्यायाधीश न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया ने अपने निर्णय में कहा कि सरकारी सेवाओं में दस फीसद क्षैतिज आरक्षण देना नियम विरुद्ध है, जबकि न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी ने अपने निर्णय में आरक्षण को संवैधानिक माना। फिर यह मामला सुनवाई हेतु दूसरी कोर्ट को भेजा गया। उसने भी आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। साथ में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16 में कहा गया कि सरकारी सेवा के लिए नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। इसलिए आरक्षण दिया जाना असंवैधानिक है।

नहीं रह गया है, सरकार की ओर से देर से दाखिल करने का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया। यह प्रार्थना पत्र लिमिटेशन एक्ट की परिधि से बाहर जाकर पेश किया गया जबकि आदेश होने के 30 दिन के भीतर पेश किया जाना था।

राज्य आंदोलनकारियों को 2004 में एनडी तिवारी सरकार

दस फीसदी आरक्षण दिए जाने के दो शासनादेश लाई। पहला शासनादेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों के लिए, जबकि दूसरा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए था।

जीओ जारी होने के बाद राज्य आंदोलनकारियों को दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया

गया। 2011 में उच्च न्यायालय ने इस जीओ रोक लगा दी। बाद में हाईकोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील करके 2015 में इस पर सुनवाई की। खंडपीठ में शामिल दो न्यायाधीशों ने आरक्षण दिए जाने व नहीं दिए जाने को लेकर अपने अलग अलग निर्णय दिए।

सरकार ने बुधवार को राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर वाले शासनादेश में शामिल प्रावधान के संशोधन को प्रार्थना पेश किया था, जिसको कोर्ट ने ने निरस्त कर दिया। इस प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता रमन साह ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी विचाराधीन है।

पलटन बाजार में तीन कपड़ों की दुकान में चोरी

संवाददाता देहरादून। दून के पलटन बाजार में चोरों ने तीन दुकानों को निशाना बनाया। छत तोड़कर एक के बाद एक दुकान में घुसे चोरों ने नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ किया। बुधवार को देहरादून के पलटन बाजार में जंगम शिवालय के पास स्थित कपड़ों की तीन दुकानों में चोरी की घटना सामने आई। बीती रात को दुकान बंद कर घर गए दुकानदार जब आज सुबह दुकान पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि पलटन बाजार में स्थित गढ़वाल साडीज, बाबा कलेक्शन और मीनाक्षी फैशन में सीलिंग तोड़कर एक ही रात में चोरी की गई। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इसी प्रकार की घटना घंटाघर स्थित गेलाई, गुप्ता हैंडलूम और अरविंद कलेक्शन में हुई थी। व्यापारियों में रोष है कि शहर कोतवाली पुलिस और धारा चौकी की नाक के नीचे इस घटना को अंजाम दिया गया।

In a Digital World Why To wait for a Howker

Supporting Devices

All Apple Touch Phones & Tablets

All Android Touch Phones & Tablets

All Window & BlackBerry Touch Phones 10+

Visit Us at <https://www.page3news.co>.

Read News

Watch News Channel

Scan This Code

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के. प्रिंटर्स, 74/9, आराध, देहरादून
से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ.-राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादक: प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालय:
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।

(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं०
UTTHIN(2005)15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून
ही मान्य होगा।